संख्या-23/2017/1066/क0नि0प्र0/26-3-17-6(34)/2006

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर,2017
समाज कल्याण विभाग

विषय:- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वत: रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए द्वितीय किस्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्र संख्या-1959/लेखा अनुभाग/2017-18 दिनांक 14-11-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वत: रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए द्वितीय किस्त के रूप में 19,50,40,000/- (रू0 उन्नीस करोड़ पचास लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि अनुदान स्वरूप निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजना के निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन तथा धनराशि का वितरण नियमानुसार हो, इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रबन्ध निदेशक द्वारा बना ली जाय तथा इसकी मासिक रूप से मानीटरिंग करते हुए धनराशि के सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेगें।

2- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो।

4- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

6- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को यथासमय उपलब्ध कराये जायेगें। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

7- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0106-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित स्वतः रोजगार योजनाओं में अनुदान(100 प्रतिशत भारत सरकार)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें □ाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2017/1066/क0नि0प्र0/26-3-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आ□ट प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग।
6- गा□ फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in